आदर्श सब्ज़ी मंडी

नेताओं का काम वोटों के लिये कब्ज़े कराना, सत्तारूढ होने पर तोड़-फ़ोड़

बल्लबगढ (म.मो.) बस अड्डे पर स्थित आदर्श सब्ज़ी मंडी में बीते शुक्रवार यानी 22 जनवरी को भारी पुलिस बल की सहायता से नगर निगम ने बड़े पैमाने पर तोड़-फ़ोड़ की। जाहिर है इससे दुकानदारों का भारी नुक्सान हुआ। काफ़ी सामान बर्बाद हो गया, बिखर गया या लूट गया। विरोध करने एवं पुलिस पर पत्थराव करने पर करीब 40 लोग़ों को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न कड़ी धाराओं में गिरफ़्तार कर लिया गया।

विदित है कि यह सारी की सारी सब्ज़ी मंडी लोग़ों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ाई हुई है। सारी की सारी ज़मीन सरकारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिये करीब आधी दुकानों को हटाना जरूरी था, इनके न हटने से न केवल सड़क का बल्कि मैट्रो रेल का काम भी अटका पड़ा है। बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी कोई दुकानदार टस से मस होने को तैयार नहीं हुआ तो सरकार को बल प्रयोग करना पड़ा।

दरअसल तमाम सरकारी ज़मीनों की तरह यहां पर भी कब्ज़े नेताओं के संरक्षण तथा अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी के बल पर हुए थे। कभी भी कोई नेता अवैध कब्ज़ों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता। प्रत्येक यही कह कर उन्हें उत्साहित करता है कि कब्ज़े कर लो हमारी सरकार आयेगी तो देख लेंगे, कब्ज़े नहीं हटने देंगे, जान की बाज़ी लगा देंगे, आदि-आदि। ऐसे में सम्बन्धित अधिकारी आंखें मीचे रखने के बदले अपनी मुट्ठी गर्म करते रहते हैं।

अब, जब तोड़-फ़ोड़ का वक्त आया तो सत्तारूढ दल के विधायक मूल चन्द शर्मा घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच गये। कुछ झूठे-सच्चे आश्वासन दे डाले। वे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाये कि अवैध कब्ज़े करने तथा पुलिस पर पत्थराव करने वालों से सरकार सख्ती से निपटना जानती है। ऐसे ही नेताओं की बदौलत पूरे शहर की फुटपाथों पर अवैध कब्ज़े हुए पड़े हैं दुकानदारों ने अपने सामने की आधी सड़क घेर कर सामान सज़ा रखा है। कुछेक ने सामने रेहड़ी आदि खड़ी करा रखी हैं जिनसे वे किराया वसूलते हैं। ऐसे में जाम का लगना और आवागमन दूभर होना स्वाभाविक है। अपाहिज कानून लाचार तमाशाई नज़र आता है।

शहर में बढता क्राइम ग्राफ़

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनआईटी पुलिस की मिलीभगत के चलते शहर में गोरखधंधे करने वाले जमकर अपने धंधों को अंज़ाम दे रहे । शहर में चोरी लूट-पाट, महिलाओं पर बढते अपराध, सट्टेबाज़ी, शराब तस्करी, वेश्यावृत्ति रूकने का नाम तक नहीं ले रही। डी सी पी एनआईटी व ए सी पी एन आईटी के दफ़्तर के ठीक सामने बने तिकोना पार्क में जम कर सट्टा, जुआ चल रहा है। जहां निरंतर लाखों रुपये का जुआ खेला जाता है।

एनआईटी 5/एल ब्लॉक में डोली नाम की महिला जमकर देह व्यापार के धंधे को खुलेआम करवा रही है। इसके साथ ही फ्रूट गार्डन व एनएच/5 के एच ब्लॉक में साई मंदिर के साथ देह व्यापार का धंधा ज़ोरों पर चल रहा है। एन एच-5 का शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक होगा जिसमें 2-4 अवैध शराब विक्रेता न हो ये काम कोई चोरी-छिपे नहीं बल्कि दिन-दहाड़े खुलेआम हो रहा है। एनएच-3 दयानंद वूमेन कॉलेज रोड पर सारा दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जब कोई स्थानीय निवासी इन असामाजिक तत्वों का विरोध करता है तो ये उसकी इतनी बेहरमी से पिटाई करते हैं कि अगली बार कोई निवासी इनका विरोध नहीं करता। ये मुण्डा तत्व तेज़ आवाज़ की मोटरसाइकिलों से सारा दिन आतंक मचाये रखते हैं। कहने को तो एक पी सी आर वहां खड़ी रहती है, जो कि सिर्फ़ गाड़ी में बैठकर अपना काम खत्म कर चले जाते हैं। एनएच 5 सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक, जे ब्लॉक, के ब्लॉक, एम ब्लॉक, राहुल कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, गांधी कॉलोनी में करीब 30 से ज्यादा धंधेबाज अपने गोरख धंधों को अजाम दे रहे हैं।

बसें तो चला नहीं पाये बातें मैट्रो रेल की

फ़रीदाबाद (म.मो.) अभी तक तो स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ही गुड़गांव तक मैट्रो रेल चलाने की लफ़्फ़ाजी करते थे अब मुख्यमंत्री खट्टर नहर पार ग्रेटर फ़रीदाबाद को मैट्रो से जोड़ने का राग अलापने लगे हैं।

विदित है कि डी एम आर सी (दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन) भारत सरकार व दिल्ली सरकार की मिलकियत है; यानी कि इसका पूरा नियन्त्रण उक्त दोनों सरकारों के हाथ में है। और इसका प्रबन्धन पेशेवर विशेषज्ञों के हाथ में है। ये लोग कोई भी निर्णय आवश्यकता, लाभ व हानि के आधार पर लेते हैं न कि खट्टरों व कृष्णपालों की जुमलेबाज़ी के आधार पर। मुजेसर तक मैट्रो सेवा का विस्तार करके मैट्रो प्रबन्धन ज़्यादा खुश नहीं है; क्योंकि 2 लाख यात्री प्रति दिन मिलने का उनका अनुमान 50 हज़ार का आंकड़ा भी छू नहीं पाया। ऐसे में बल्लबगढ तक इसे बढाना उनको पहले ही भारी पड़ रहा है। ऐसे में यदि इन मन्त्रियों की जुमलेबाज़ी पर मैट्रो चलने लगी तो दिवाला निकलते देर नहीं लगेगी। इन मन्त्रियों को क्या जोड़ पड़ता है, ये तो हर गली-मुहल्ले तक मैट्रो चलाने का भी ऐलान कर सकते हैं।

हां, रोडवेज़ की बसें चलाना इनके ज़िम्मे जरूर हैं। वे इनसे चलती नहीं। पूरे राज्य भर में शायद ही कोई डिपो ऐसा हो जो भारी घाटे तले ना हो। घाटे में हो भी क्यों न जब सारे नेता और अफ़सर भ्रष्ट और निकम्मे हों। दूर जाने की जरूरत नहीं फ़रीदाबाद डिपो की अपनी 150 बसें व जवाहर लाल नेहरू फंड की 200 बसों में से आज यहां 100 बसें भी सही सलामत चलने की हालत में नहीं है। वर्कशॉप में न तो मिस्त्री हैं और न ही आवश्यक कल-पुर्जे। जो बस थोड़ी सी खराब हो गयी वह मुरम्मत के अभाव में पूरी तरह खराब ही होती चली गयी।

वर्कशॉप के लिये आवश्यक कल-पुर्जों की तमाम खरीदारी पहले डिपो का जी एम (महाप्रबन्धक) ही अपने स्तर पर कर लिया करते थे। लेकिन नेताओं व उच्चाधिकारियों को यह रास नहीं आया; क्योंकि खरीद पर मिलने वाला कमीशन बड़े आकाओं को वसूलने में दिक्कत होती थी। इसलिये उन्होंने राज्य भर की सारी खरीद सीधे अपने हाथ में ले ली। इससे सारा कमीशन एकमुश्त सीधे उनके हाथ में आने लगा। लेकिन यह काम इतना जटिल हो गया कि महीनों तक वर्कशॉपों में आवश्यक सामान नहीं पहुंचता।

इसी तरह मिस्त्री, ड्राइवर व कंडक्टरों की भर्ती का जो काम पहले जी एम खुद अपने स्तर पर कर लिया करते थे, वह भी उनके हाथ से छीन कर चंडीगढ में बैठे बड़े आकाओं ने अपने हाथ में ले लिया। भर्ती करने से रिश्वतखोरों को रिश्वत या ईमानदार को जो भलाई मिलती थी वह सब नेताओं ने अपने हाथ में ले ली। इन नेताओं को इतनी 'फ़ुर्सत' नहीं होती कि वे समय पर स्टाफ़ की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकें क्योंकि इनको तलाश रहती है अपने 'वफ़ादार' चमचों व दलालों की, जिनके मार्फ़त ये लोग सारा काम करते हैं। खर्चा घटाकर मुनाफ़ा बढाने के नाम पर नियमित स्टाफ़ की जगह भर्ती किये जा रहे हैं ठेके पर। 70-80 लाख की बस खरीद कर उस (ठेकेदारी) ड्राइवर कंडक्टर के हवाले कर दी जाती है जिसकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं होती। हो भी कैसे सकती है जब वह है ही कच्ची नौकरी पर, वह भला क्यों बस के रख-रखाव में रूचि लेने लगा? सरकार के मुकाबले में चल रही कैपिटल बस सर्विस एवं ऐसी अन्य किसी भी बस कम्पनी में इस तरह का स्टाफ़ भर्ती नहीं किया जाता। सारा स्टाफ़ नियमित और पक्का होता है जो आयुपर्यन्त वफ़ादारी से नौकरी करता है और कम्पनी मुनाफ़ा कमाती हैं।

सरकार एवं इन मन्त्रियों की नीयत यदि ठीक होती तो ये लोग जुमलेबाज़ी और आये दिन नारियल फ़ोड़ने का धंधा छोड़ कर कुछ ढंग का काम करते, लेकिन वह इन्होंने कभी करना नहीं। ये तो केवल जुमलेबाज़ी ही कर सकते हैं।

मज़दूरों की एकता के सामने झुका प्रबंधन

फ़रीदाबाद (इन्कलाबी) फ्लैस इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा. लि. के मज़दूरों ने अपनी एकता से कम्पनी प्रबन्धन को झुकने पर मजबूर कर दिया। सेक्टर 27 बी के प्लांट नं. 3, 8 व 9 में स्थित कम्पनी ने दोनों प्लांटों ने नया ग्रेड देने का नया फ़ार्मूला अपनाया। इसके बाद मज़दूरों ने संघर्ष शुरू किया। कम्पनी में गाड़ियों का गीयर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक पार्ट बनते हैं।

ज्ञात हो कि हरियाणा सरकार ने लम्बे समय बाद न्यूनतम वेतन की समीक्षा करते हुए न्यूनतम वेतन 7600 से 9700 रुपये तक घोषित कर दिया है जिसे 1 नवम्बर से लागू करना था। उपरोक्त कम्पनी महीने की 7-8 तारीख को वेतन भुगतान करती है। कम्पनी ने 8 दिसम्बर 2015 को नवम्बर माह का वेतन देते समय नया फ़ार्मूला अपनाया जो आश्चर्य करने वाला था। कम्पनी प्रबन्धन ने श्रम कानूनों का खूलेआम उल्लंघन करते हुए 10 घंटे का कार्य दिवस के हिसाब से नवम्बर माह का वेतन बनाया। प्रबंधन की इस नीति का मज़दूरों ने जोरदार विरोध किया। 9 दिसम्बर को मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने कम्पनी मैनेजर से बात की। कम्पनी प्रबन्धन ने मज़दूरों की बातों को अनसुना कर दिया। मज़दूरों ने उसी दिन शाम को आपस में बात कर प्रबंधन को सबक सिखाने का प्रण किया। अगले दिन यानी 10 दिसम्बर को कम्पनी के अंदर आकर काम बन्द कर दिया और मांग की कि उनका वेतन नये ग्रेड तथा 8 घंटे कार्य दिवस के हिसाब से दिया जाय अन्यथा वे काम नहीं करेंगे।

मज़दूरों के इस साहसिक कदम से कम्पनी मैनेजर पगला गया और मज़दूरों को गालियां बकने लगा तथा अपने सिक्योरिटी गार्डों को ललकारा कि मज़दूरों को पीटो। मज़दूर कम्पनी से बाहर हो गये और जुलूस निकालकर, सेक्टर-15 फ़रीदाबाद में स्थित उपश्रमायुक्त के कार्यालय की ओर चल दिये। दिन की पारी के लगभग 170 मज़दूर 10 किलोमीटर की दूरी पैदल ही चलकर उपश्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे। रास्ते में मज़दूरों ने कम्पनी प्रबन्धन के खिलाफ़ नारे लगाये। बता दें कि कम्पनी दो शिफ्ट में चलती है। तथा इसमें लगभग पौने चार सौ मज़दूर काम करते हैं।

श्रम कार्यालय पहुंच कर मज़दूरों ने लिखित में अपनी शिकायत दी। उस दिन डी.एल.सी. महोदय ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मज़दूरों का जमावड़ा देखकर ऑफिस के कर्मचारी हरकत में आ गये। उन्होंने डी.एल.सी. महोदय को फ़ोन किया फ़िर कम्पनी मैनेजर से फ़ोन पर बात की। इसके बाद कम्पनी तुरंत ही मज़दूरों की मांग मानते हुए नया ग्रेड देने को राज़ी हो गयी तथा मैनेजर ने मज़दूरों को वापिस कम्पनी बुलाया।

10 दिसम्बर जिस दिन शिकायत दी गयी, मज़दूर कम्पनी नहीं गये। अगले दिन 11 दिसम्बर 15 को सभी मज़दूर कम्पनी में दाखिल हुए तथा बोले कि जब तक उनका हिसाब नहीं बनेगा वे काम नहीं करेंगे। लगभग 2 -ढाई घंटे काम बंद रहा फ़िर कम्पनी का मालिक आया तथा हिसाब बनाने की घोषणा की। तब जाकर मज़दूरों ने काम शुरू किया। अगले दिन मज़दूरों का बकाया वेतन मिल गया।

मोदी की तर्ज पर खट्टर की विदेश यात्राएं...उर्फ घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने

-वाई. के. रज्जन

लेकिन खट्टर की विदेश यात्रा का जो डंका बाहर पीटा जा रहा है वह है केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे है जिसके बारे में कंपनियों को बताया जा रहा है कि आइए मानेसर, बावल में कंपनी लगाइए, केएमपी बस तैयार होने वाला है। हरियाणा शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचएसआईडीसी) की देखरेख में बनने वाला केएमपी प्रोजेक्ट वक्त से दस साल पीछे चल रहा है। यानी जिस प्रोजेक्ट को दस साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसे पूरा करने का डंका यह सरकार पीट रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश में किसी को विदेश यात्रा का शौक है तो वह हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में विदेशी कंपनियों को लाने की बहाने ये भाई इतनी विदेश यात्राएं कर रहा है कि इससे थोड़ा सा ऊपर मोदी की विदेश यात्रा है। दोनों की यात्राओं के बाद भारत अब महाशक्ति बनने वाला है। देश में लाखों युवकों की नौकरी लगने वाली है। देश में ऐसी बहार आने वाली है कि चारों तरफ बस जन्नत के नजारे होंगे। ....सपने देखने में क्या हर्ज है।

विदेश की कोई कंपनी अगर भारत में आती है तो वह देखती है कि उस शहर का ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास कैसा है, जिसमें सड़कों की हालत, बिजली, पानी, हाउसिंग आदि पर खास तवज्जो दी जाती है। हरियाणा में जब बीजेपी सरकार बनी तो खट्टर ने पहली घोषणा की कि हमे सड़कों के पुराने गड्ढे सबसे पहले भरने हैं यानी सरकार का पहला काम होगा राज्य की सड़कों का सुधार करना। फरीदाबाद, गुड़गांव के गिने-चुने शहरी इलाकों में आप जरूर कुछ सड़कों को बनता हुआ देख रहे होंगे लेकिन जैसे ही आप गांवों की तरफ बढ़ेंगे तो आप को सड़कों की जो बदहाली नजर आएगी, उससे आपको इस सरकार की असलियत पता लग जाएगी। सड़कों को बनाने का इस सरकार के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सेक्टर 28 स्थित घर के आसपास सेक्टरों को देखेंगे तो आपको सड़कें बनती नजर आएंगी लेकिन बाईपास रोड जिसका इस्तेमाल रोजाना हजारों वाहन कर रहे हैं, जिनकी सड़कों पर गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं, उस सड़क को बनाने की कोई योजना नहीं है। पीडब्ल्यूडी और फरीदाबाद नगर निगम अपनी-अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सेक्टर 8, 9, 10 फरीदाबाद में नजर डालेंगे तो ऐसी ही हालत मिलेगी। गुड़गांव ओल्ड सिटी की हालत फरीदाबाद जैसी ही है। अब धारूहेड़ा, बावल, झज्जर इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो वहां की हालत फरीदाबाद-गुड़गांव से भी बदतर मिलेगी। सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र का जिक्र ही क्या करें। हां, सीएम सिटी के कारण करनाल में भी आपको काम होता हुआ दिखेगा। ...लेकिन खट्टर की विदेश यात्रा का जो डंका बाहर पीटा जा रहा है वह है केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे है जिसके बारे में कंपनियों को बताया जा रहा है कि आइए मानेसर, बावल में कंपनी लगाइए, केएमपी बस तैयार होने वाला है। हरियाणा शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचएसआईडीसी) की देखरेख में बनने वाला केएमपी प्रोजेक्ट वक्त से दस साल पीछे चल रहा है। यानी जिस प्रोजेक्ट को दस साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसे पूरा करने का डंका यह सरकार पीट रही है। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में केएमपी का ठेका केएमपी एक्सप्रेसवेज नामक कंपनी को मिला था। यह कंपनी लागत बढ़ाती रही और हुड्डा सरकार के अफसर एचएसआईडीसी के जरिए कमीशन खाते रहे। एक दिन इस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। एचएसआईडीसी ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर सलाह लेने के लिए एक अनजान सी कंपनी मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा. लि. को लाखों रुपये दिए। उसने लाखों रुपये लेकर बताया कि केएमपी एक्सप्रेसवेज ने जितना काम किया है उसको 1300 करोड़ रुपये दे दिए जाएं। और फिर नया ठेका किसी और कंपनी को देकर काम करा लिया जाए। हालांकि कुछ अफसरों ने दबी जबान से इसका विरोध किया लेकिन उनकी कौन सुनता है। हुड्डा सरकार ने इस पेमेंट को मंजूर भी कर लिया। इसके बाद राज्य में बीजेपी सरकार आ गई। नई सरकार ने 19 मार्च 2015 को केएमपी एक्सप्रेसवेज का ठेका कैंसल कर दिया। यह गंभीर जांच का विषय है कि हुड्डा से लेकर खट्टर सरकार तक इस प्रोजेक्ट पर जितना खर्च किया गया है, उससे प्रोजेक्ट में हासिल क्या किया गया। बहरहाल, इसके बाद खट्टर ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। फौरन नए ठेकेदार का इंतजाम हो गया। हरियाणा सरकार ने केसीसी बिल्डकॉन प्रा. लि. और दिलीप बिल्डकॉन प्रा. लि. को यह ठेका दे दिया। लेकिन बताया गया कि केएमपी के एक हिस्से का ही काम इन दोनों कंपनियों को मिला है। दोनों कंपनियों का आपस में जॉइंट वेंचर है। कोई नहीं जानता कि यह सब गोरखधंधा क्या है। सूत्र बताते हैं कि केएमपी एक्सप्रेसवेज अभी भी नई कंपनियों की आड़ में काम कर रही है। यानी सामने दिखाने और कमीशन खाने का जो धंधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के वक्त चल रहा था, वही धंधा अभी भी चल रहा है। बीच में एचएसआईडीसी सिर्फ चेक काटने का काम करती है। *शेष पेज सात पर*